का इतिहास प्रसिद्ध किला नितान्त शोचनीय स्थिति में है ;

(ख) क्या यह सच है कि उसकी सफाई, मरम्मत और सुरक्षा की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्राचीन स्मारक की सुरक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि चित्तौड़ के किले में यात्रियों के निवास के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है, इसके कारण जो भी यात्री किला देखने जाते है, परेशान होकर वापिस होते हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, डाक बंगला है, उसमें यात्री लोग ठहर सकते हैं और मेरे ख्याल में वह काफ़ी अच्छी सुविधा है ।

श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि चित्तौड़ के कुछ प्रमुख नागरिकों ने वहां पर यात्रियों के निवास के लिए एक धर्मशाला बनाने का प्रस्ताव रखा है और क्या इस सम्बन्ध में उन्होंने सरकार से कोई सहायता मांगी है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मेरे पास ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया है अगर आयेगा तो उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : कुछ वर्ष पहले चित्तौड़ के स्थान को और अधिक रमणीय और आकर्षक बनाने की एक योजना तैयार की गई थी, मैं जानना चाहता हूं कि उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, यदि माननीय सदस्य चित्तौड़ जाकर देखें तो पायेंगे कि इन पिछले तीन सालों में उसकी तस्वीर बिल्कुल बदल गई है और जो पुराने खंडहर थे उनकी मरम्मत कर दी गई है और काफी अच्छी हालत में उनको कर दिया गया गया है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि मीराबाई का जो प्रसिद्ध मन्दिर चित्तौड़ के किले में है उसमें एक मूर्ति स्थापना के लिए सरकार विचार कर रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी नहीं ।

श्री प० ला० बाकलीवाल : माननीय मंत्री ने अभी बतलाया कि डाक बंगले में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है तो क्या मैं जान सकता हूं कि डाक बंगले में किस श्रेणी के व्यक्ति ठहर सकते हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : डाक बंगले में सभी लोग ठहर सकते हैं ।

श्री प० ला० बाकलीवाल : किसान भी ठहर सकते है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : वहां ठहरने का पैसा देना पड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसान भी वहां पर ठहर सकते हैं सिर्फ पैसा देना पड़ता है ।

श्री प० ला० बाकलीवाल : कितना पैसा देना पड़ता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह तो बहुत मुश्किल है ।

State Finance Ministers' Conference

\+

*913. **Shri Bimal Ghose:**
Shri Tangamani:
Shri Assar:
Sardar Iqbal Singh:
Shri S. M. Banerjee:
Shri N. R. Munisamy:

Will the Minister of Finance be pleased to lay on the Table a statement showing:

(a) the agenda of the State Finance

Ministers' Conference held in Delhi on the 18th November, 1957;

(b) whether it has been agreed at the Conference to replace sales tax on commodities by additional excise duty;

(c) if so, what are the commodities concerned;

(d) other decisions arrived at in the Conference; and

(e) the steps Government propose to take to implement these decisions?

The Deputy Minister of Finance (Shri B. R. Bhagat): (a) A copy of the press communique setting out the subject for discussion at the conference issued on the 12th November, 1957 is placed on the Table of the Lok Sabha. [See Appendix III, annexure No. 94].

(b) to (e). The discussions at the conference were informal and confidential and no decisions as such were taken. The various matters considered at the meeting are being processed further in the light of the views expressed at the meeting.

Shri S. M. Banerjee: May I know whether any decision was taken to exempt foodgrains from the sales-tax to help lowering down of the prices and, if so, whether the State Governments have agreed to this?

Shri B. R. Bhagat: No, Sir.

Shri Basappa: May I know whether the Indian Coffee Board has recommended to the Government that the sales tax on coffee may be replaced by additional excise duty and, if so, whether the Government is considering that question?

Shri B. R. Bhagat: It never came up for discussion in the Conference.

Shri B. S. Murthy: May I know whether the question of small savings was discussed and, if so, what steps are proposed to be taken for having a better and effective drive in that line?

Shri B. R. Bhagat: Yes, Sir. This matter was generally discussed in the Conference.

Shri B. S. Murthy: I wanted to know whether any steps were taken in respect of the drive for small savings.

Mr. Deputy-Speaker: The information available is only so much that this matter was discussed.

Shri N. R. Munisamy: May I know whether in view of certain decisions as regards the prevention of evasion of taxes as well as the collection of income-tax arrears, any concrete proposals have been put forward by the Ministers as to the investment of certain extra powers in the Income-Tax Officers in the States to collect the taxes due to the Union, with a view to collect the entire tax on this behalf by issue of certificates by them?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): Certain difficulties that are in the way have been pointed out to the State Finance Ministers and we have obtained from them the assurance that all possible cooperation, to the extent that it can be possible and is necessary, will be forthcoming.

Shri Rameshwar Tantia: May I know whether the news in the newspapers that sales-tax will be abolished on sugar, cloth and such things is true and, if so, what will happen to the stocks which are lying with the dealers?

Shri T. T. Krishnamachari: When a decision of that nature is taken, then I think the question will arise.

Shri Panigrahi: May I know whether the State Finance Ministers were asked to increase their revenue from new taxes and what was the reaction of the State Governments?

Mr. Deputy-Speaker: That would not be covered by this restricted question.

Shri Heda: May I know whether many of the State Finance Ministers expressed the view that their revenues

from sales-tax would be augmented by about five times more if they are replaced by the additional excise duty and, if so, are the Government proposing to take any steps thereon?

Shri T. T. Krishnamachari: The matter was generally discussed, as I said. Whether the income will be augmented or not depends upon the nature of the steps that are taken. It would be rather premature for me to discuss the matter at this stage.

Ch. Ranbir Singh: May I know whether the Conference considered the replacement of the outmoded land revenue system by some progressive taxation policy?

Mr. Deputy-Speaker: Sales-tax is sought to be removed in lieu of certain additional excises. Next question.

Shri B. R. Bhagat: I am sorry it is a long answer in Hindi.

Mr. Deputy-Speaker: If he has prepared it, he might read it.

अफीम फैक्टरी, गाजीपुर

*६१४. **श्री सरजू पाण्डे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) गाजीपुर जिले की अफीम फैक्टरी के पास कितनी एकड़ भूमि है ;

(ख) क्या यह सच है कि पोलीटैक्नीक इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इंस्टीट्यूट के विस्तार के लिए भूमि देने के सम्बन्ध में प्रार्थना की थी;

(ग) यदि हां, तो कितनी एकड़ भूमि की मांग की गयी थी और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार अफीम फैक्टरी की बेकार ज़मीन पर कोई फैक्टरी निर्माण करने का विचार कर रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा०)भक्त : (क) ११५ एकड़ ।

(ख) पोलीटेक्निक इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के पास से सीधे कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया था । उत्तर प्रदेश के उद्योग निदेशक (डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज) ने उत्तर प्रदेश सरकार की मार्फत केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की थी कि वह पोलीटैक्निक के विस्तार के लिए, गाजीपुर अफीम डिवीजन की बेकार भूमि और इमारतें उक्त संस्था को दे दें ।

(ग) जितने एकड़ भूमि मांगी गयी थी उसका विवरण इस प्रकार है :

(१) कार्यालय भवन और गोदाम	२८२२६.८८ वर्गफुट
(२) भवन के साथ छोड़ी जाने वाली भूमि	६.३७ एकड़

राज्य सरकार को भूमि तथा इमारतें सौंप देने की बात को अन्तिम रूप दिया ही जाने वाला था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, गाजीपुर के जिला इंजीनियर ने गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर को यह सुझाव दिया कि टूटी फूटी दशा में होने के कारण ये इमारतें पोलीटेक्निक इंस्टीट्यूट के लिए न ली जायं । गाजीपुर के कलक्टर ने यह सुझाव अवश्य रखा कि राज्य सरकार इन इमारतों को केवल इस शर्त पर खरीद सकती है कि केन्द्रीय सरकार इनकी कोई कीमत न मांगे क्योंकि, उनके विचार से, ये इमारतें, टूटी फूटी होने के कारण, बोझ ही अधिक है । गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर का यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इमारतों की कोई कीमत लिये बिना ही इन इमारतों और भूमि का हस्तांतरण कर दिया जाय, क्योंकि केन्द्रीय सरकार की इमारतों को, मूल्य लिये बिना किसी राज्य को दे देने की अनुमति नहीं है ।

(घ) नहीं । उस बेकार भूमि पर कोई कारखाना खोलने का केन्द्रीय सरकार का विचार नहीं है ।